Impact Factor-7.675 (SJIF) ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refreed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

November-2020

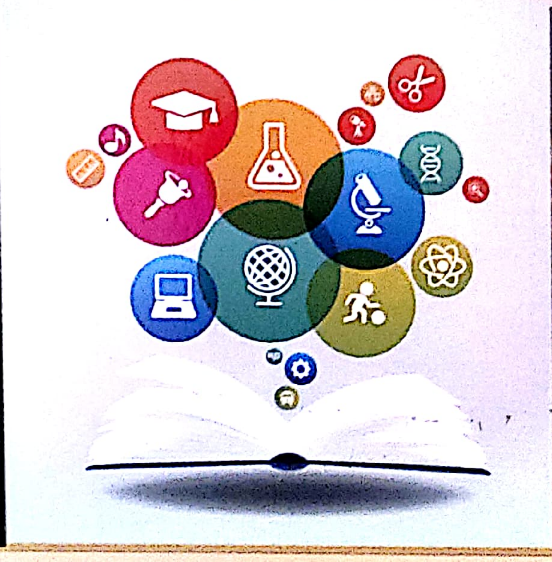

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor:
Dr.Dinesh W.Nichit
Principal
Sant Gadge Maharaj
Art's Comm,Sci Collage,
Walgaon.Dist. Amravati.

Executive Editor:
Dr.Sanjay J. Kothari
Head, Deptt. of Economics,
G.S.Tompe Arts Comm,Sci Collage
Chandur Bazar Dist. Amravati

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar Publications

(SJIF) Impact Factor-7.675

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

November-2020

SPECIAL ISSUE-CCLIV (254)

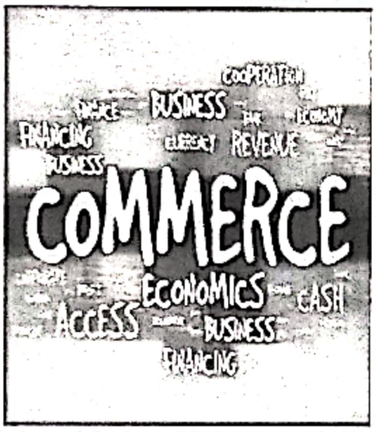

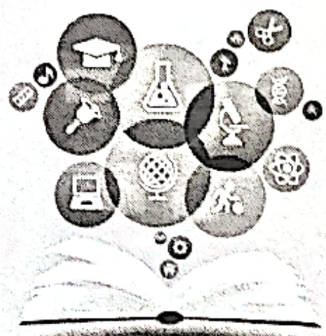

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social Research & Development Training Institute Amravati

Editor:
Dr.Dinesh W.Nichit
Principal
Sant Gadge Maharaj Art's Comm,Sci Collage, Walgaon.Dist. Amravati.

Executive Editor :
Dr.Sanjay J. Kothari
Head,Deptt.of Economics,
Head, Deptt. of Economics,
G.S.Tompe ArtsComm,Sci Collage
Chandur Bazar Dist. Amravati

The Journal is indexed in:

Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

Cosmos Impact Factor (CIF)

International Impact Factor Services (IIFS)

Impact Factor – 7.675 ISSN – 2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

November,2020

ISSUE No – CCLIV (254 - A)

Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Language & Law

Prof. Virag.S.Gawande
Chief Editor :
Director
Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

Dr.Dinesh W.Nichit
Editor :
Principal
Sant Gadge Maharaj Art's Comm,Sci Collage, Walgaon.Dist. Amravati.

Aadhar International Publications

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

© All rights reserved with the authors & publisher

INDEX

No.	Title of the Paper / Authors' Name	Page No.
1	शिवाजी—इस्लाम संबंध — प्रा. मंगेश वाहाणे	1
2	गोपीनाथराव मुंढे यांचे सामाजिक कार्य — प्रा.झरेकर रमेश सोनू	5
3	साने गुरूजींचे अनुवादित साहित्य — डॉ. जयश्री शास्त्री	9
4	भटक्या विमुक्तांच्या साहित्याची भाषा : विशेष संदर्भ 'पालावरचं जग' — प्रा. गणेश दिगंबर सावजी	14
5	धरण प्रभावित क्षेत्रातील विस्थापित कुटूंबाच्या समस्या — संजय नामदेवराव तोरवणे / प्राचार्य.डॉ.डी.एस.पाटील	18
6	स्त्री भ्रुणहत्या कारणे व उपाययोजना — सौ. किर्ती नितीन सांगळे	22
7	मानवाधिकार आणि आदिवासी समाज — प्रा.डॉ.उल्हास एन राठोड	25
8	राजे लखुजी जाधवराव कार्य व कर्तुत्व— एक समालोचन — रविंद्र शंकरराव फटींग	30
9	इक्कीसवीं सदी के महिला उपन्यासकारों के उपन्यासोंमें चित्रित नारी — डॉ.प्रमोद परदेशी	36
10	भारतातील बौद्धीक संपदा अधिकाराचे महत्व व फायदे : एक दृष्टीक्षेप — संशोधक प्रा. सचिन ग, कर्णेवार / डॉ. प्रशांत म. पुराणिक	42
11	युवावर्गातील फास्ट फुडचे वाढते आकर्षण : आरोग्याची एक भीषण समस्या — प्रा. डॉ. सोनाली राजेश बन्सोड	46
12	जागतिकीकरण आणि शिक्षण यांच्यातील तुलनात्मक अभ्यास — प्रा. डॉ. मंजुषा समर्थ	50
13	वहामनी सुलतान व नरसिंगदेव राय संघर्षातून हिंदू राज्य स्थापनेचे प्रयत्न — डॉ. गजेन्द्र बी. ढवळे	54
14	भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारः एक वास्तव — डॉ. आर. जी. बांबोळे	58
15	मंदोदरीबाई पाटीलयांचे जागृति वृत्तपत्रातील स्त्री सुधारणेविषयक विचार — प्रा. सचिन ज्ञानेश्वर मोरे	63
16	महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यातील अनुसूचित जमाती मधील 'आंध' समुदायाची बोलीभाषा — प्रा. गणेश बंडूजी माघाडे	66
17	कोव्हिड - १९ मधील प्लाझ्मा दान आणि लोकभ्रम — प्रा. कमलेश मानकर	74
18	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे आरोग्यासंबंधी विचारांची कोरोना काळामध्ये गरज — प्रा. डॉ. अनुराधा रा. मुळे	79

19	बौध्द मनोविज्ञान : अभिधमत्थसंगहो डॉ. मनोहर कुंभारे	84
20	भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर जाण्याची कारणे डॉ. केशव सुर्यभानसा गुल्हाने	88
21	कोविड-१९ आणि मानसीक अस्वस्थता डॉ. कमल रविंद्र पोटदुखे	91
22	राजर्शी शाहू महाराजांचे शिक्षण विषयक विचार आणि कार्य प्रा.डॉ.विठ्ठल जीवतोडे	94
23	स्त्रीवादी समीक्षा : बदलते आयाम डॉ. नरेंद्र घरत	99
24	वर्धा जिल्हयातील तालुकानिहाय लोकसंख्या वाढीचे भौगोलिक विश्लेषण प्रा. एन. जी. सोनुले	104
25	राजर्षी शाहू महाराजांचे पाणी व्यवस्थापन व शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग संगशेट्टी आर एम	112
26	पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचे आर्थिक विचार प्रा. डॉ. देवेंद्र शिवदास रंगाचार्य	118
27	आदिवासींच्या समस्या प्रा. डॉ. नलिनी भगत	120
28	कोरोना : भारतातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती. प्रा. विशाखा मानकर	123
29	एक नजर धारा ३७० के क्रियान्वयन पर हर्ष कुमार	127
30	'तत्त्वज्ञान म्हणजे विज्ञानाचे तर्कशास्त्र' ह्या ए. जे. एयरच्या मताच्या समर्थनार्थ प्रा. सुमेरू गोंडाणे	131
31	आर्थिक परिस्थितीचा गर्भवती स्त्रिच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कु. सीमा देशमुख / डॉ. विभा काटे	135
32	वृध्दांच्या समस्या : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास प्रा.डॉ.आव्हाड भगवान भानुदास	139
33	भारतीय संघराज्य में क्षेत्रीयवाद की समस्या विशेष संदर्भ पृथक् राज्यों की मांग डॉ.नागेश खुशालराव गायकवाड	143

B.Aadhar' International Peer-Reviewed Indexed Research Journal | ISSN : 2278-9308
Impact Factor - ((SJIF) -7.675, Issue NO, 254 (A) | November,2020

भारतीय संघराज्य में क्षेत्रीयवाद की समस्या विशेष संदर्भ पृथक् राज्यों की मांग

डॉ.नागेश खुशालराव गायकवाड
असिस्टंट प्रोफेसर एस.पी.एम. तात्यासाहेब महाजन आर्टस् एण्ड कॉमर्स कॉलेज, चिखली
जि. बुलडाणा (महाराष्ट्र)

विकासशील समाजों की एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता पर आधारित 'परम्परागत निष्ठाओं' की ओर जाता है जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं।

- क्षेत्रीयतावाद का अर्थ

क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे–से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, आदि कारणों से अपने पृथक् अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं।

'क्षेत्र' शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी 'सांस्कृतिक समानता' है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को भी 'क्षेत्र' के आधार पर सम्बोधित किया जा सकता है और कालान्तर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अभिधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। किसी भी भू–भाग को क्षेत्र कहने के लिए कतिपय तत्वों का होना आवश्यक है, किन्तु आज तक उन तत्वों का ठीक तरह से निर्धारण नहीं हो सका। यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएं तथा धारणाएं समाज के अन्य भागों से भिन्न हों और लगातार काफी समय से, चाहे अलग–अलग मात्रा में सही, चली आ रही हों तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र कहा जा सकता है। ये प्रक्रियाएँ और धारणाएं भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, रीति–रिवाज सम्बन्धी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की स्थिति, रहन–सहन के ढंग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इत्यादि पर आधारित हो सकती है, परन्तु किसी भी क्षेत्र के पृथक् स्वरूप के लिए प्रमुख बात वहां के लोगों में आपसी समानता और एकरूपता तथा अन्य क्षेत्रों से अलगाव की भावना है। इस प्रकार अनेक तत्वों; जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति–रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन–सहन के तरीके, आदि की अन्त:क्रियाओं से किसी क्षेत्र (त्महपवद) का निर्माण हो सकता है। प्रो. श्रीराम माहेश्वरी का मत है कि क्षेत्र इनसे भी कुछ अधिक होता है, क्षेत्र के लोगों में साथ रहने की भावनात्मक एकता होती है और दूसरों से अपने की पृथक् मानने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका मतलब है कि वह अपने को महाराष्ट्रियनों से थोड़ा भिन्न मानता है चाहे सभी महाराष्ट्रियन यह महसूस करते हों कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लोग भिन्न हैं। ऐसी भावनाएं सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं और उनसे कोई भी आसान से मुक्त नहीं हो सकता।

भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है— राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रान्त की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहद् भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थो की पूर्ति होना है। भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती हैं। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है जो कि प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थिति आन्दोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है।

- भारत में क्षेत्रीयतावाद : ऐतिहासिक विरासत

क्षेत्रवाद आज भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में एक अत्यन्त व्यापक घटना है और कम से कम निकट भविष्य में जनसाधारण के मस्तिष्क से इस धारणा के दूर होने के कोई चिन्ह दिखायी नहीं देते। आधुनिक युग में संचार व्यवस्था के नए साधनों, अंग्रेजी—प्रशासन व्यवस्था के तरीके और नीतियों, उपनिवेशवाद से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् आधुनिकीकरण को अत्यधिक महत्व और तीव्रता प्रदान करने की प्रक्रियाओं ने, क्षेत्रवाद और अन्य तनावो को अधिक सचेत और सक्रिय किया है।

भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है अपितु वैचारिक, परम्परा, धर्म, संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने भारत की इस सामाजिक—सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया। स्वतन्त्रता की बेला पर भारत दो भागों में विभक्त था— ब्रिटिश भारत के प्रान्त एवं देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना तो जाग्रत हुई, किन्तु ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं किया। अपितु अपने न्यस्त हितों को ध्यान में रखकर किया। देशी रियासतों में थोड़ी—बहुत आन्तरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया। स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। इस सन्दर्भ में प्रारम्भिक रूप से दो समस्याएं सामने आयी— राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अन्तर्गत केन्द्र—राज्य सम्बन्धों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनर्सीमांकन एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। आगे चलकर भारत में सरकारी भाषा, शिक्षा के माध्यम, राजस्व और स्त्रोतों के बंटवारे, इत्यादि के प्रश्नों को लेकर क्षेत्रवाद की भावना में बढ़ोत्तरी होती गयी।

- भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद के कारण

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं:—

१ भौगोलिक २ सांस्कृतिक ३ ऐतिहासिक ४ आर्थिक कारण ५ भाषा ६ जति ७ राजनीतिक कारण

- भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर की जा सकती है

१. क्षेत्रीयतावाद और पृथक् राज्यों की मांग, २. क्षेत्रीयतावाद बनाम अन्तर्राज्यीय झगड़े: ३. क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग, ४. क्षेत्रीयतावाद और केन्द्र—राज्य संघर्ष, ५. क्षेत्रीयतावाद के सन्दर्भ में उत्तर—दक्षिण की भावनाएं, ६. क्षेत्रीयतावाद के सन्दर्भ में भाषावाद, ७. क्षेत्रीयतावाद और भारतीय संघ से पृथक् होने की प्रवृत्ति, ८. क्षेत्रीयतावाद और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अभ्युदय।

ISSN : 2278-9308
November,2020

- क्षेत्रीयतावाद और पृथक् राज्यों की मांग

क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक् राज्य की मांग रही है। आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक् राज्य की मांग समय–समय पर उठायी गयी तथा क्षेत्रीय आन्दोलनों की शुरुआत की गयी। पृथक् राज्यों की मांग के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संघीय इकाइयों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है। इसी मांग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को १९७० में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा जनवरी १९७२ में त्रिपुरा एवं मणिपुर को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया। १९८७ में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। दिल्ली के लोग भी पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। दिसम्बर १९९१ में दिल्ली के लिए ७–सदस्यीय विधानसभा तथा ७–सदस्यीय मंत्रिपरिषद् के निर्माण से संबंधित विधेयक संसद ने पारित कर दिया, परन्तु केन्द्रशासित क्षेत्र के रूप में दिल्ली का दर्जा बन रहेगा। २००० में और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीन राज्यों की मांग पूरी हुई।

आज तेलंगाना देश का २९वां राज्य बन चुका है। २७ अगस्त, २०१३ को यूपीए समन्वय समिति के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने भी इस पर मुहर लगा दी। ३ अक्टूबर, २०१३ को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने भी अलग राज्य के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी। मन्त्रिमण्डल का यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश विधानसभा को भेजा। १८ फरवरी, २०१४ को भाजपा के सहयोग से लोकसभा में २० फरवरी, २०१४ को राज्यसभा में तेलंगाना विधेयक पारित हो गया जिसे १ मार्च, २०१४ को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई। आन्ध्र प्रदेश के बंटवारे से नया राज्य तेलंगाना २ जून, २०१४ से अस्तित्व में आया। ये राज्य हैं — आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मई २०१४ के लोकसभा चुनावों के साथ–साथ दोनों राज्यों में विधानसभाओं के भी चुनाव सम्पन्न करवाये गये। तेलंगाना विधानसभा में ११९ सदस्य तथा आंध्र प्रदेश विधानसभा में १७५ सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त पृथक् राज्यों की मांग को निम्नलिखित संदर्भ में देखा जा सकता है।

राज्यों का पुनगर्ठन— सन् १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों के पुनगर्ठन का मुख्य कारण भाषायी राज्यों की ही मांग थी। भाषागत राज्यों की मांगों ने राष्ट्रव्यापी असन्तोष को जन्म दिया। इसके द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रवादी लोगों में यह आशंका पैदा हुई कि इससे देश छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता का अन्त हो जाएगा।

बम्बई राज्य का विभाजन— बम्बई राज्य के विभाजन की मांग तीव्रतर होने लगी। यह मांग की जाने लगी कि गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर राज्य को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। सन् १९६० में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई।

पृथक् विदर्भ राज्य की मांग— सन् १९६० के आस–पास पृथक् विदर्भ राज्य की मांग की जाने लगी। नागपुर के लोगों का कहना था कि महाराष्ट्र की स्थापना से नागपुर का महत्व कम हो गया, क्योंकि उससे पूर्व नागपुर मध्य भारत की राजधानी था।

पंजाब राज्य का पुनर्गठन— सन् १९६६ में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया परिणामतः पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ का संघीय प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश एक प्रशासनिक इकाई बन गया। हिमाचल प्रदेश एक प्रशासनिक इकाई बन गया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी राज्यों का तेजी से आर्थिक विकास करना और वहां की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करना था।

ISSN : 2278-9308
November,2020

असम राज्य का पुनर्गठन– सितम्बर १९६८ में असम पुनर्गठन की एक योजना घोषित की गयी थी। इस योजना में राज्य के पहाड़ी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी जिससे पहाड़ी लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों और विकास सम्बन्धी क्रिया–कलाप बढ़ सकें। 'असम पुनर्गठन (मेघालय) बिल' दिसम्बर १९६८ में पारित होकर कानून बन गया और असम राज्य के अन्तर्गत 'मेघालय' का स्वायत्तशासी राज्य स्थापित हो गया।

भूतपूर्व संघीय प्रदेशों–मणिपुर तथा त्रिपुरा के लोग भी अधिक स्वायत्त शासन की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और असम के मिजो जिले की जनता के लिए एक पृथक् प्रशासनिक इकाई की मांग पर विचार किया। प्रदेश की सुरक्षा और आर्थिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए गए। इन परिवर्तनों को अमल में लाने के लिए १९७२ में एक अधिनियम पारित किया गया और मणिपुर एवं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

आज बोडो, गारो और कार्बी जैसी जनजातियां भी असम से अलग हो जाने की भाषा बोल रही है।

२००० नए राज्यों का निर्माण– २५ मार्च, १९९८ को राष्ट्रपति ने संसद को सम्बोधित करते हुए कहा था कि सरकार उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, बिहार में वनांचल और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ बनाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए विधेयकों का प्रारूप तैयार किया गया। २० अगस्त, १९९८ को राष्ट्रपति महोदय ने उक्त विधेयकों को भारत के संविधानक सम्बन्धित विधानमण्डलों को भेजा था। राज्य विधानमण्डलों के विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् लोकसभा में दिसम्बर १९९८ में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक १९९८, बिहार पुनर्गठन विधेयक और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक १९९८, बिहार पुनर्गठन विधेयक और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक १९९८ पेश किए गए।

अगस्त २००० में संसद द्वारा पारित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य (१ नवम्बर, २०००) में वर्तमान मध्य प्रदेश के १६ जिले सम्मिलित हैं। अगस्त २००० में संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० पास करके उत्तरांचल राज्य के निर्माण को स्वीकृति दे दी तथा ९ नवगठित उत्तरांचल राज्य के निर्माण को स्वीकृति दे दी तथा ९ नवगठित उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश के १३ जिले शामिल किए गए हैं। अगस्त २००० में ही संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित करके झारखण्ड राज्य के निर्माण (१५ नवम्बर, २०००) को स्वीकृति दे दी।

- अन्य भागों में पृथक् राज्यों की मांग

वर्ष २००० में उपर्युक्त तीन नए राज्यों के गठन के बाद भी आठ नए राज्यों के गठन के लिए पुरजोर मांग की जा रही थी – उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, हरित प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, असम में बोडोलैण्ड तथा पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड।

अगर किसी ने ऐसा सोचा था कि उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ बन जाने के बाद भारत का संघीय मानचित्र पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, तो उसे पुनर्विचार करना होगा। हाल की घटनाओं से यही लगता है कि नए राज्यों के गठन की सम्भावनाएं फिर जोर पकड़ रही हैं। अगर अभी नही तो कभी निकट भविष्य में ये साकार हो सकेंगी। इसका स्पष्ट संकेत विदर्भ कांग्रेस और नए राज्यों के राष्ट्रीय मोर्चे का एक साथ गठन होने से मिलता है हो सकता है कि विदर्भ राज्य के मुद्दे पर साठे और साल्वे की घोषणा से कांग्रेस पार्टी को कोई झटका लगा हो, लेकिन हरित प्रदेश, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड की मांगें भी अचानक सामने नहीं आई हैं। इनकी मांग तो काफी समय से थी, लेकिन साठे और साल्वे की पहल और राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना से इन

मांगों ने पुनः सुर्खियों में आ जाने की स्थिति बन गई है। देखा जाए तो यह पहला मौका है कि पांच नए राज्यों की मांग करने वालों ने मिलकर अपना एक मोर्चा बनाया।

इन मांगों को चाय के प्याले में तूफान के रूप में देखना आसान है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी छोटे राज्य की मांग उठी है, उसकी ऐसी ही उपेक्षा की गई है, बाद में भले ही राज्य का गठन हो गया हो। हो सकता है कि लोग भूल गए हों लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव के आधार पर प्रान्तों को नया रूप देने के बाद से करीब एक दर्जन राज्यों की स्थापना हो चुकी है। अब दिल्ली सहित एक दर्जन नए राज्यों की मांग सामने है। हो सकता है कि राष्ट्रीय मोर्चा जिन पांच राज्यों की मांग कर रहा है, उनका वास्तव में आधार हो। फिर भी अनेक विद्वान छोटे राज्यों के पक्ष में हैं और उनका मानना है कि उनसे लोकतन्त्र मजबूत होगा और विकास में तेजी आएगी। गत वर्षों के दौरान कतिपय प्रमुख विद्वान कुछ बहुत बड़े प्रशासनिक तामझाम वाले राज्यों को छोटा करने की बात पर जोर देते रहे हैं। कुछ राज्य तो आकार या जनसंख्या के लिहाज से वास्तव में भीमकाव हैं। यह भी कोई संयोग नहीं कि ऐसे राज्य ही सबसे लचर शासन वाले और सबसे पिछड़े हैं।

- हर कोने से राज्य की मांग

उत्तर प्रदेश:

पश्चिम उत्तर प्रदेश २२ जिलों को मिलाकर हरित प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। राज्य के दक्षिणी हिस्से के ७ और मध्य प्रदेश के ६ जिलों में बुन्देलखण्ड बनाने की मांग हो रही है। पूर्व मुख्यमन्त्री मायावती ने भी कई मौकों पर बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और पश्चिम क्षेत्र में एक अन्य राज्य बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र तीन राज्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति देता है तो उन्हें विधानसभा में इसे पारित कराने में हिचक नहीं होगी। समाजवादी पार्टी इसके विरोध में रही है। नवम्बर २०११ में उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव पारित कराने के साथ ही तात्कालीन मुख्यमन्त्री मायावती ने राजनीतिक रूप से गेंद केन्द्र के पाले में डाल दी। विधानसभा की कार्यवाही मात्र १६ मिनट चली। इसमें भी राज्य को चार भागों (पश्चिमी प्रदेश, अवध प्रदेश और पूर्वांचल) में बांटने जैसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव सिर्फ २५ सेकण्ड में पारित करा लिया।

विदर्भ:

नागपुर और अमरावती संभाग को मिलाकर बना महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र। उत्तर में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश के लगे इस क्षेत्र में राज्य की लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या होती है। सन्तरे और कपास के उत्पादन के लिए मशहूर यह क्षेत्र शेष महाराष्ट्र की तुलना में पिछड़ा है। किसानों की आत्महत्या को लेकर चर्चा में रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विदर्भ को महाराष्ट्र से पृथक् करने की मांग की जा रही है। भाजपा एवं कांग्रेस के सांसद पूर्व में पृथक् राज्य के लिए संसद में निजी बिल भी पेश कर चुके हैं। शिवसेना इसका विरोध कर रही है।

गोरखालैण्ड:

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और पर्वतीय व तराई के क्षेत्रों में अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में १९८६ से १९८८ के बीच चले आन्दोलन के बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउन्सिल की स्थापना हुई। गोरखालैण्ड जनमुक्ति मोर्चा पृथक् राज्य के लिए आन्दोलनरत है। पार्टी के ३ विधायक हैं। अब फिर वहां धरने प्रदर्शन किये गए हैं। माकपा इस मांग का विरोध करती है।

B.Aadhar' International Peer-Reviewed Indexed Research Journal
Impact Factor - ((SJIF) –7.675, Issue NO, 254 (A)
ISSN : 2278-9308
November,2020

बोडोलैण्ड:

असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के क्षेत्र को बोडोलैण्ड के नाम से अलग करने की मांग की जा रही है। लगभग ८,७९५ वर्ग किसी क्षेत्र में राज्य के कोकराझार, बक्सा, चिराग, उदलगुड़ी चार जिले आते हैं जहां क्षेत्रीय भाषा 'बोडो' बोली जाती है अस्सी के दशक में वहां आन्दोलन शुरू हुआ जो हिंसक भी हो गया। १० फरवरी, २००३ को एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत बोडो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। स्थानीय बोडो पार्टियां और संगठन पृथक् बोडो राज्य के लिए आन्दोलन चला रहे हैं।

जम्मू—कश्मीर:

विहिप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने प्रस्ताव पारित कर जम्मू—कश्मीर को तीन भागों में बांटने का सुझाव दिया है। इसके अनुसार जम्मू, कश्मीर पृथक् राज्य और लद्दाख को स्वायत्शासी परिषद बनाया जाए। हालांकि इस मांग का कई राजनीतिक दल विरोधी भी कर रहे हैं।

कार्बी—आंगलांग:

१०,४३४ वर्ग किमी क्षेत्र का असम का यह सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या १० लाख के लगभग है। अलग राज्य के लिए आगजनी, प्रदर्शन का दौर जारी है। इस राज्य के समर्थक अपने विरोधियों पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद का घर जला दिया गया। दो लोग मारे जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल:

पश्चिम बंगाल में कूच—राजवंगशिस लोग 'कामतापुर' राज्य की मांग कर रहे हैं। ये लोग उत्तरी बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये 'कामतापुरी' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं।

कर्नाटक:

कर्नाटक में 'कोडगू (कुर्ग)' राज्य की मांग की जा रही है। कोडगू कर्नाटक राज्य के दक्षिण—पश्चिम हिस्से का सबसे छोटा जिला है। पहले राज्य पुनगर्ठन आयोग की सिफारिश पर इसे भाषायी आधार पर मैसूर (वर्तमान में कर्नाटक) के कन्नड़ स्टेट के साथ मिलाया गया था।

गुजरात:

गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के उद्योगपति व व्यवसायी पिछले सात वर्ष से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

सबसे ज्वलन्त उदाहरण बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो इतनी है कि अगर अलग देश बन जाए तो उसका विश्व में नौवां स्थान हो। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जिन पांच नए राज्यों की स्थापना की मांग की जा रही है। उनमें तीन तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। इन तीन राज्यों में एक बुन्देलखण्ड ऐसा है कि उसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आएगा। इन राज्यों और महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग का विरोध जिन आधारों पर किया जा रहा है, वे तर्कसंगत नहीं। यह कहा जाता है कि नए—नए राज्य बनाने से भारत के टुकड़े—टुकड़े हो जाएंगे। नए राज्य सक्षम नहीं होंगे और केन्द्र अपनी मनमानी थोप सकेगा। ज्यादा राज्य होने से अन्तर—राज्य विवाद ज्यादा होंगे और हर नए राज्य के गठन से शासन करने का प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा, जिससे जनता पर भार में वृद्धि ही होगी। ये आशंकाएं निराधार हैं।

- **निष्कर्ष**

नए राज्यों का गठन होने से भारत के टुकड़े—टुकड़े होने की बात जो करते हैं, उन्हें इस बात का कतई भान नहीं कि पृथकतावाद को जन्म देने वाले कारक क्या होते हैं। अगर राज्यों की संख्या पर ही देश की राष्ट्रीय एकता टिकी हो तो ५० पूर्ण स्वायत्तता वाले राज्यों से बना

ISSN : 2278-9308
November,2020

अमरीका तो कब का टूटकर बिखर गया होता। नए राज्यों के गठन से देश की अखण्डता को भी कोई खतरा नहीं। इसी प्रकार छोटे राज्यों के समक्ष नहीं हो पाने के तर्क में भी दम नहीं है। पहले असम–नेफा था जहां अब सात राज्य है और उनमें कोई अक्षम नहीं है। यही बात पंजाब के बारे में है। उसमें से अलग होने के बाद हरियाणा की तो तस्वीर ही बदल गई है। केन्द्र–राज्य सम्बन्धों की बात भी निराधार है। छोटे राज्यों में लोकतन्त्र ज्यादा कारगर होता है। अन्तर्राज्य विवादों को सुलझाना कठिन अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि कावेरी विवाद को सुलझाने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक का विलय कर दिया जाए।

प्रशासनिक खर्च बढ़ने की बात में कुछ दम है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि छोटे राज्य होने से समस्याएं और चुनौतियां भी कम होंगी। अगर वास्तव में हमें खर्च की चिन्ता है तो कुछ सुधारों से खर्च को कम किया जा सकता है। राजनेताओं और नौकरशाहों को सार्वजनिक धन के प्रति लापरवाही का रवैया छोड़ना होगा। मन्त्रिमण्डल तथा प्रशासन के आकार के बारे में कोई हदबन्दी होनी चाहिए। मन्त्रियों और उच्चाधिकारियों को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं में लगातार वृद्धि ही होती गई है। विधान परिषद के रूप में सफेद हाथी (कुछ राज्यों में अब भी) पालने की कोई जरूर नहीं है।

अक्सर कहा जाता है कि भारत में बड़े राज्य हैं, परिवहन में दिक्कत होती है। इसलिए छोटे राज्य होने चाहिए। लेकिन यह तर्क बहुत हद तक गलत है। भारत में एक राज्य का क्षेत्रफल औसतन १,१०,००० हजार वर्ग किलोमीटर है, जबकि अमरीकी राज्य का इससे दो–गुना और ब्राजील में तीन गुना है। असल में नए राज्य की मांग विकास के अभाव और कुप्रबन्धन से जुड़ी है। गोरखालैण्ड, विदर्भ, बोडोलैण्ड, बुन्देलखण्ड, कार्बी आंगलांग इत्यादि सभी देश के पिछड़े क्षेत्र हैं। अगर पुराने राज्यों को ही विकसित कर दिया जाए तो नए राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. जैन पु., डॉ. फाडीया बी (२०१५) भारतीय शासन एवं राजनीति, आगरा: साहित्य भवन, सी. १७ साईट सी सिकन्दरा, औद्योगिक क्षेत्र।
2. कौशिक सुरेंद्र (१९४८) राजनीति विज्ञान, आगरा; उपकार प्रकाशन
3. कुमार अशोक (१९९७) राजनीति विज्ञान, आगरा; उपकार प्रकाशन
4. डॉ. गाबा. ओ.पी. (२०००) विवेचनात्मक राजनीति विज्ञान, नई दिल्ली;, नैशनल पब्लिशिंग हाउस
5. डॉ. सिंह बी.पी. (२००२) शासन, एवं राजनीति, नई दिल्ली; ज्ञानदा प्रकाशन

Impact Factor-7.675 (SJIF) ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refreed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

Human Rights : Reality & Challanges

SPECIAL ISSUE

December-2020

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor:
Dr. Sandip B. Kale
Coordinator
HOD. Dept. Of Political Science
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo
Dist. Wardha

Executive Editor:
Dr. Archana S. Dahane
Officiating Principal
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo
Dist. Wardha

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar Publications

(SJIF) Impact Factor-7.675

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refreed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

December-2020

SPECIAL ISSUE-No-CCLVIII (258)

Human Rights : Reality & Challanges

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor:
Dr. Sandip B. Kale
Coordinator
HOD. Dept.Of Political Science
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo
Dist. Wardha

Executive Editor :
Dr. Archana S. Dahane
Officiating Principal
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo
Dist. Wardha

The Journal is indexed in:

Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

Cosmos Impact Factor (CIF)

International Impact Factor Services (IIFS)

Impact Factor – 7.675 ISSN – 2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refreed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

December - 2020

SPECIAL ISSUE – (CCLVIII) 258

Human Rights : Reality & Challanges

Prof. Virag.S.Gawande
Chief Editor :
Director
Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

Dr. Sandip B. Kale
Editor:
Coordinator
HOD. Dept of Political Science
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo ,Dist.Wardha(M.S)

Dr. Archana S. Dahane
Executive-Editors
Officiating Principal
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo,Dist.Wardha(M.S)

Aadhar International Publication

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

© All rights reserved with the authors & publisher

B.Aadhar' International Peer-Reviewed Indexed Research Journal | ISSN : 2278-9308
Impact Factor - ((SJIF) -7.675, Issue NO, 258 | December,2020

INDEX

No.	Title of the Paper	Authors' Name	Page No.
1	महिला आणि मानवी हक्क	प्रा.हर्षला सूर्यवंशी	1
2	बालमजुरी आणि मानवाधिकार – एक दृष्टीक्षेप	प्रा.राजेंद्र घोरपडे	5
3	मानवी आरोग्याच्या दृष्टिकोणातून मानवी हक्क	प्रा.डॉ.शुद्धोधन एस. गायकवाड	9
4	मानवाधिकार आणि बालकामगार	प्रा.डॉ. नितीन दादाराव गौरखेडे	14
5	'मानवाधिकार : जेष्ठ व्यक्ती(वृध्द व्यक्ती) सद्यस्थिती एक विश्लेषनात्मक अध्ययन	प्रा.डॉ.यु.आर.धुमाळे	17
6	मानवाधिकाराच्या अंतर्गत आदिवासीच्या ओळखीच्या समस्येचा अभ्यास	प्रा. डॉ. महेंद्र पाटील	21
7	मानवाधिकार आणि भारतीय संविधान	डॉ. सुधाकर सोनोने	25
8	मानवी हक्क आणि युनोची वाटचाल	प्रा.डॉ.नागेश खु.गायकवाड	29
9	मानवाधिकाराच्या दृष्टीकोनातून भारतामध्ये महिलांच्या सबलीकरणासाठी करण्यात आलेल्या विविध तरतूदीचे अध्ययन	प्रा. डॉ. मनिषा यादव	32
10	संयुक्त राष्ट्रसंघटना व मानवी हक्क	प्रा. डॉ. अनंत रिंढे	36
11	मानवी हक्क आणि भारतीय संविधान	प्रा. डॉ. अविनाश पांचाळ	39
12	मानवीय हक्क आणि लिंगभाव समानता	कु.दिप्ती गोपाळराव नेहर	44
13	बालकामगार आणि मानवी हक्क	प्रा.दत्तात्रय मुकूंदराव ढवारे	54
14	मानवाधिकार और चिकित्सा सेवा जीवन का आधार एक विवेचन	डॉ.रमेश टी. बावनथडे	59
15	**आदिवासी जमाती आणि मानवी हक्क**	**बळीराम शेषेराव चव्हाण / स्नेहा राजेंद्र माने**	63
16	भारतीय संविधान आणि मानव अधिकार	प्रा. डॉ. अतुल हणमंत कदम	62
17	मानवाधिकार आणि स्त्रिया	डॉ. प्रा. अश्विनी अविनाश खापरे,	72
18	बालकांचे मानवी हक्क	डॉ. आशिष दि. काळे	75
19	भारतीय समाज में महिला मानवाधिकारों की वर्तमान दशा एवं दिशा	डॉ. अर्चना डी. पाटील	78
20	मानवी हक्क आणि दलित अत्याचार : एक अध्ययन	प्रा. डॉ. आनेराव एम.एम.	81
21	मानवीधिकार व भारतीय संविधान	डॉ. प्रमोद मा. आचेगावे	86
22	बालकामगार व मानव अधिकार	सहा. प्रा. राहुल जे. जोंधळे	88

B.Aadhar' International Peer-Reviewed Indexed Research Journal
Impact Factor - ((SJIF) -7.675, Issue NO, 258
ISSN : 2278-9308
December,2020

'मानवी हक्क आणि युनोची वाटचाल'

प्रा.डॉ.नागेश यु.गायकवाड
राज्यशास्त्र विभागप्रमुख
शि.प्र.मं.तात्यासाहेब महाजन कला व वाणिज्य महाविद्यालय, चिखली.जि.बुलडाणा

प्रस्तावना :-

विश्वामध्ये जेंव्हा राष्ट्रे एकमेकांचे शत्रू बनुन लढत होते. तेंव्हा प्रे.विल्सन यांच्या कल्पनेतून 'राष्ट्रसंघ' नावाची वैश्विक संघटना उदयाला येत होती. पहिल्या महायुध्दामध्ये जेंव्हा लोकशाही समर्थन करणारे विरुध्द हुकूमशाही राजसत्ता असलेले राज्य एकमेकांच्या विरुध्द लढत होते, तेंव्हा प्रचंड जिवित व वित्त हाणी झाली. त्यातुन अनेक राज्यांचा विजय ही झाला, परंतू झालेल्या हाणीमुळे अनेक राष्ट्रामध्ये अंतर्गत समस्या निर्माण झाल्या, म्हणून ही वेळ पुन्हा येऊ नये व आलेल्या समस्यांचा एकत्रीत सामना करण्यासाठी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष प्रे. विल्सन यांनी राष्ट्रसंघ नावाच्या संघटनेच्या स्थापनेसाठी जगाला आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत जानेवारी १९२० ला राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली. खऱ्या अर्थाने जागतिक शांततेच्या दृष्टिने टाकलेले हे पहिले पाऊल होते. परंतू राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेपासुनच त्याच्या कमकुवतपणाचा प्रत्यय येत होता. त्यामुळे राष्ट्रसंघाला दुसरे महायुध्द रोखता आले नाही. परिणाम दुसऱ्या महायुध्दात प्रंचड प्रमाणात मणुष्य व वित्त हाणी घडून आली.

दुसऱ्या महायुध्दात होत असलेल्या विनाशामुळे मानवाच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण झाले. म्हणुनच तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डी.रुझवेल्ट व इंग्लडचे तत्कालीन पंतप्रधान विस्टन चर्चिल यांनी एकत्र येवून प्रथमतः युनोच्या स्थापनेची कल्पना मांडली. अनेक राष्ट्रांना आपले सोबत घेवुन २४ ऑक्टोंबर १९४५ ला संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना केली. खरे पाहिले तर युनोच्या स्थापनेपासुनच मानवाच्या हक्कांचे जागतीक व्यासपीठ तयार झाले, नंतर युनोच्या मार्गदर्शनामध्ये अनेक जागतीक संघटना तयार झाल्या आणि त्यावर युनोने मानवी कल्याणाच्या दृष्टिने अनेक अटीची पुर्तता ही केली.

मानवहित आणि युनोची स्थापना :-

विश्वामध्ये दोन महायुध्दाने संपुर्ण राज्यांची अवस्था कमकुवत केली होती, ते मानव हितापासुन परावृत्त होऊन केवळ शत्रु राष्ट्रापासुन संरक्षण करणे ऐवढे कार्य करण्यावरच भर देऊ लागले, परिणाम मानवहिताकडे संपुर्ण जगाचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळेच अनेक राष्ट्र एकत्र येवुन त्यांनी मानव कल्याणाच्या दृष्टिने आंतरराष्ट्रीय विधी, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जगातील प्रत्येक मानवाचा आर्थिक सामाजिक तथा राजकीय विकास, शैक्षणिक व वैज्ञानिक प्रगती इत्यादी बाबींकडे संपुर्ण जगाचे लक्ष वेधले, आणि युनोची स्थापना केली. युनोने पुढे मानवी हित जोपसण्याच्या दृष्टिने आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना व मानवी हक्क जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

मानवाधिकारचे वैश्विक घोषणापत्र :-

हे युनोच्या आमसभेने दि. १० डिसेंबर १९४८ रोजी पॅरिस येथे स्विकारलेले घोषणापत्र आहे. हे घोषणापत्र दुसऱ्या महायुध्दात जगाने अनुभवलेल्या नृशंस अत्याचारांचा परिणाम म्हणून अस्तित्वात आले. सर्व मानवांच्या जन्मसिध्द मानवाधिकारांची पहिली जागतीक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. यात एकुण ३० कलमे असुन त्यांचा सविस्तर अर्थ नंतर झालेल्या अनेक करारांमधून राष्ट्रीय घटना आणि कायदे यातून आणि स्थानिक मानवाधिकार संघटनाकडून लावण्यात आला आहे. याच घोषणापत्रावर आधारित 'मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक' १९६६ मध्ये आमसभेत मांडण्यात आले. १९७६ मध्ये त्यास कायद्याचे स्वरुप प्राप्त झाले.

युनोच्या स्थापनेपासुन युनोने मानवी हक्काबाबत नेहमीच जागृक राहुन केवळ मानवी कल्याणाच्या दृष्टिनेच प्रयत्न केल्याचे आढळते. यामध्ये प्रामुख्याने मानवी हक्काचे घोषणापत्र, आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क

कायदा इत्यादी सोबत वेळोवेळी मानवी हक्कांचे पालन करण्यासाठी अनेक राज्यांवर घातलेले बंधने हे मानवी हिताच्या दृष्टिने अंत्यत हितकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मानवी हक्क संरक्षणाच्या दृष्टिने युनोची वाटचाल :-

द्वितीय महायुध्दानंतर विश्वामध्ये जिथे-तिथे मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली तिथे प्रत्येक ठिकाणी युनोने हस्तक्षेप करुन मानवी हक्क संरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसते. परंतू यामध्ये सुरक्षा समितीतील पाच स्थायी सदस्यांची भूमिका फार महत्त्वपुर्ण राहिलेली आहे त्याचीच वास्तविकता जानुन घेणे या शोध निबंधाचे मुख्य उद्दीष्टे आहे. मानवी हक्क संरक्षणाच्या दृष्टिने मानवाधिकार आयोग स्थापित असुन जगातील सर्व देशामध्ये मानवी हक्क संरक्षणासाठी कार्य करत आहे. आवश्यक त्या सुधारणासह मानवी हक्क संरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहे.

- **UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) :-**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेची एक कार्यात्मक समितीच्या रुपात १९४६ ला स्थापना करण्यात आली होती. जिचे मुख्य कार्य निवेदन तयार करणे, अधिकारा संदर्भात आंतरराष्ट्रीय बिल, नागरीक स्वतंत्रता, स्त्रीयांची स्थीती व मानवाधिकार इत्यादी विषयावर सल्ला देणे तथा प्रश्न उपस्थित करणे असे होते.

डिसेंबर १९९३ मध्ये युनोच्या महासभेने मानवाधिकारा संदर्भात घडणाऱ्या घटनांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मानवाधिकार उच्च आयुक्ताचे पद निर्माण केले. तेंव्हा पासुन आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्च आयुक्तांच्या नेतृत्वात कार्यरत होता. परंतू दि.१५ मार्च २००६ ला पुन्हा युनोच्या महासभेने मानवाधिकार आयोग पुनर्रचित करण्याच्या दृष्टिने नविन प्रस्ताव मांडला आणि त्यात पुर्वीच्या ५३ सदस्यिय आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची जागा ४७ सदस्यीय मानवाधिकार परिषदेने घेतली. अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दि.१६ जुन २००६ रोजी समाप्त करण्यात आला.

- **UNHRC ची स्थापना :-**

दि.१६ जुन २००६ रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेची प्रत्यक्ष बैठक आयोजित करण्यात आली. तेंव्हापासुन या परिषदेचे कार्य सुरु झाले ही परिषद स्थायी असुन ती युनोच्या महासभेच्या अधिनस्थ राहून कार्य करण्यासाठी बांधील असल्याचे नमुद केल्या गेले.

कार्य : - १) जागातील कोणत्याही देशातील मानवी अधिकार उल्लघंनाचे विश्लेषण करते.

२) वेळोवेळी आपल्या कार्याचा अहवाल युनोच्या सर्व घटकांना सादर करावा लागतो.

या परिषदेचे सर्व कार्यकरण्यासाठी ती सार्वाभीम असेल व तिला निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता व आंतरराष्टीय सिंध्दातावर आधारित कार्य करावे लागते.

"Promotion and Protection of Human Rights around the globe"

या स्लोगनला अनुसरुन गेली पंधरा वर्षे ही संस्था युनोच्या मार्गदर्शनात मानवी हक्क संरक्षणाचे काम करत आहे.

मानव अधिकाराची अंमलबंचावणी :-

जेंव्हा एखादे लोकसत्ताक सरकार लोकांचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता सदासर्वकाळ आणि सर्वस्वी आपल्या नियंत्रावर ठेवते तेंव्हा ती लोकसत्ता राहत नाही. ती अनियंत्रीत हुकूमशाहीच होते . त्यामुळे अशा लोकसत्ताक प्रशासनावर नियंत्रण असणे हेही संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महत्वाचे कार्य आहे. मानवी अधिकाराच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक देशातील शासन व्यवस्था ही महत्वपूर्ण बाब आहे. निक्सन फोर्ड आणि कार्टर या अमेरीकच्या अध्यक्षांनी 'मानवी हक्क ' या संकल्पनेचा अमेरिकेच्या फायद्यासाठी उत्तम राजकीय वापर केला आहे आणि रोनाल्ड रिगण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्याहीपुढे जाऊन खऱ्या अर्थाने मानवी हक्काचा प्रभावी वापर साम्यवाद संपविण्यासाठी करुन भांडवलवाद निर्माण करण्यासाठी केला आहे.

अलीकडे रशीया,चिन या साम्यवादी तथा सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांनी सुध्दा मानवी हक्क संरक्षणाच्या नावाखाली राजकराणच केल्याचे अलीकडील अनेक घटनांवरुन दिसते.

निस्कर्ष :-

२० व्या शतकात झालेल्या दोन महायुध्दामुळे मानव जातीचे प्रंचड प्रमाणात नुकसान झाले. सोबतच सामाजिक दृष्ट्या मागास देशांवर तथा हुकूमशाही वृत्तीच्या राज्यांमध्ये मणुष्य प्राण्यांवर जंगली प्राण्याप्रमाणे अत्याचार झाले. त्याचा उद्रेक होऊन युनोच्या स्थापनेनंतर,१९४६ ला स्थापन झालेल्या मानवी हक्क संरक्षण समितीद्वारे मानवी संरक्षण केले जावे,अशी धारणा झाली व लगेच १० डिसेंबर १९४८ मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसीध्द करुन अधिकारांची निश्चिती करण्यात आली. पुढे या आधारावरच १९६६ ला आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्याचा मसुदा सादर करुन पुढे पारीत करण्यात आला. १९९३ ला मानवी हक्काचे

ISSN : 2278-9308
December,2020

संरक्षण करण्याच्या हेतूने महासभेद्वारे उच्च आयुक्त पदाची निर्मिती करुन १६ जुन २००६ ला UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेची) स्थापना करण्यात आली. आज त्याद्वारे मानवी हक्क संरक्षणासाठी कार्य सुरु आहे.

१. मानवी हक्क संरक्षणासाठी युनोने वेळोवेळी पुढाकार घेतला.
२. मानवी हक्कांचे निश्चितीकरण मानवी हक्क घोषणापत्राद्वारे करण्यात आले.
३. मानवी हक्क संरक्षित करण्यासाठी युनोद्वारे वेळोवेळी अधिनियम तयार केल्या गेले.
४. मानवी हक्क संरक्षणाच्या नावाखाली सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांद्वारा स्वराष्ट्राचा फायदा केला.
५. स्थायी संदस्यांनी मानवी हक्क संरक्षणाच्या नावाखाली गैरफायदा घेवु नये यासाठी UNHRC स्वायत्त संस्था स्थापित करण्यात आली.
६. सध्यस्थितीत जगातील कोणत्याही देशात मानवी हक्कांचे अवमुल्यन झाल्यास UNHRC द्वारा विश्लेपन केले जाते.

संदर्भ :-

१. डॉ वैद्य सुमन, आधुनिक जग, साईनाथ प्रकाशन, नागपुर - २०००.
२. कांबळे उध्दव, मानवी हक्क - तत्व आणि दिशाभूल, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, २००७ .
३. डॉ. गवई सुभाष, डॉ.पांडे, डॉ. दया, ओळख मानवधीकाराची, वेदमुद्रा प्रकाशन,२०११
४. www.ohchr.org
५. www.Urcenter.org
६. www.un.org

IMPACT FACTOR (SJIF) 2021= 7.380

SRJIS

ISSN 2319-4766

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

APRIL-JUNE,2021, VOL - 10, ISSUE - 53

Special Issue of Department of Political Science, Lokmanya Mahavidyalaya Warora, Dist. Chandrapur (MS)

Contemporary India's Foreign Policy: Special Reference SAARC Countries

Chief Editor

Dr. Subodh Kumar Singh

Principal

Editor

Assit. Prof. Tanaji S. Mane

HOD, Department of Political Science

IMPACT FACTOR (SJIF) 2021= 7.380 ISSN 2319-4766

An International Peer Reviewed & Refereed Journal

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

APRIL-JUNE, 2021, VOL- 10, ISSUE-53

Special Issue of Department of Political Science, Lokmanya Mahavidyalaya Warora, Dist. Chandrapur

On

CONTEMPORARY INDIA'S FORIGN POLICY: SPECIAL REFERENCE SAARC COUNTRIES

Chief Editor

Dr. Subodh Kumar Singh
Principal

Editor

Assit. Prof. Tanaji S. Mane
HOD, Department of Political Science

© : AUTHOR

Edition : **Book** 2021

Disclaimer: We do not warrant the accuracy or completeness of the Information, text, graphics, links or other items contained within these articles. We accept no liability for any loss, damage or inconvenience caused because of reliance on such content. Only the author is the authority for the subjective content and may be contacted. Any specific advice or reply to query on any content is the personal opinion of the author and is not necessarily subscribed to by anyone else.

Warning: No part of this book shall be reproduced, reprinted, or translated for any purpose whatever without prior written permission of the Editor. There will be no responsibility of the publisher if there is any printing mistake. Legal aspect is in Warora jurisdiction only in favour of Editor in Chief for this Special Issue on **CONTEMPORARY INDIA'S FORIGN POLICY: SPECIAL REFERENCE SAARC COUNTRIES**

NOTE: Conference proceeding publication / Special issue publication/ Book with ISBN/ **Edited Book with ISBN publication** Contact us on **9881595917** either send your proposal to **srjisarticles16@gmail.com**

An International Peer Reviewed & Refereed

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

S. No. 5+4/5+4, TCG'S, Saidatta Niwas, D-Wing, Ph - II,
1st Floor, F. No. 104, Nr. Telco Colony & Blue Spring Society,
Dattanagar-Jambhulwadi Road, Ambegaon (BK), Pune – 411046.
Website: www.srjis.com

IMPACT FACTOR (SJIF) 2021= 7.380 ISSN 2319-4766

An International Peer Reviewed & Refereed Journal

SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

APRIL-JUNE, 2021, VOL- 10, ISSUE-53

Index

SR. NO.	TITLE & AUTHORS NAME	PAGE NO.
1	**USA, RUSSIA AND CHINA: CHANGING DYNAMICS OF SOUTH ASIA** *Dr. Rajkumar Singh*	1-4
2	**INDIA'S ROLE IN SAARC** *Dr. Basweshwar Bhimrao Pandagale*	5-8
3	**ROLE OF INDIA IN SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION** *Dr. Bharat L. Rathod*	9-13
4	**INDIA'S NUCLEAR DOCTRINE AND POLICY: EVOLUTION** *Dr. Hanumant Kurkute*	14-17
5	**INDIA'S NEIGHBOURHOOD POLICY IN THE POST COLDWAR ERA** *Dr. Sushanta Kumar Singh*	18-24
6	**HINDI STUDIES IN CHINA AND BILATERAL COOPERATION: SOME IMPORTANT OBSERVATIONS** *Anirban Ghosh*	25-30
7	**INDIA – PAKISTAN RELATIONS SINCE INDEPENDENCE** *Dr. Shriram Yerankar*	31-35
8	**INDIA -SAARC 2020-2021** *Mrs. Meenal M Rajdev*	36-39
9	**CITIZENSHIP AMENDMENT ACT 2019 & INDIA-BANGLADESH BILATERAL RELATIONS: PROSPECT AND CHALLENGES** *Soumalya Ghosh*	40-43

23	सार्क संघटनेची समकालीन प्रासंगिकता *डॉ . एन. आर. चिमुरकर*	116-120
24	दहशतवाद संदर्भात सार्कची भूमिका *प्रा. डॉ. नागेश खु.गायकवाड*	121-123
25	भारत-पाकिस्तान संबंध *डॉ. पी. एस. लोखंडे*	124-126
26	सार्क संघटनेचे योगदान *डॉ. प्रमोद मा. आचेगावे*	127-130
27	दक्षिण आशियाई राष्ट्राच्या विकासात सार्कची संघटनेची भूमिका *प्रा. डॉ. राहुल दत्ता मांडणीकर*	131-134
28	दक्षिण आशियाच्या विकासासाठी सार्क संघटनेची आवश्यकता : एक अध्ययन *डॉ. राजेंद्र ओ. बेलोकार*	135-138
29	सार्क संघटना आणि भारताची भूमिका *प्रा. डॉ. राजेंद्र सदाशिव मुद्दमवार*	139-143
30	भारत व भूतान यांचे परराष्ट्र धोरण *प्रा. डॉ. राजेंद्र एम. झाडे*	144-146
31	भारताचे समकालीन परराष्ट्र धोरण : सार्क संगठना *डॉ. सचिन एस वेरुळकर*	147-152
32	समकालीन भारत—पाक संबंध *डॉ. संदीप बी. काळे*	153-157
33	भारत-नेपाळ संबंधांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून अभ्यास *डॉ. संजय काशिनाथ पाटील*	158-161
34	*भारत-मालदिव संबंधाचे विश्लेषण* *डॉ. संतोष संभाजी डाखरे*	162-166
35	सार्क आणि भारत *डॉ. एस.पी. वेल्हाळ*	167-173

दहशतवाद संदर्भात सार्कची भूमिका

प्रा. डॉ. नागेश खु.गायकवाड
राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, शि.प्र.मं.तात्यासाहेब महाजन कला व वाणिज्य महाविद्यालय,
चिखली.जि.बुलडाणा.४४३२०१

आज संपुर्ण विश्वामध्ये सत्तेसाठी गलिच्छ राजकारण होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातच विकसित राष्ट्रे आपल्या आर्थिक संपन्नतेचा फायदा घेऊन मागास राष्ट्रांना मदत करतात व त्यांच्या संपूर्ण शासकीय व्यवहारावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचा परिणाम विकनसनशिल राष्ट्रांसोबत मागास राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दृष्टिने स्वातंत्र्य राहत नाही. असा प्रकार दुसऱ्या महायुध्दानंतर मोठया प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. त्याचे कारण दुसऱ्या महायुध्दात रशीया व अमेरीका सोबत लढले, परंतु एकमेकांना विश्वासात न घेता लढले.त्यात अमेरीकेने रशियाला अंधारात ठेवून बॉम्ब निर्मिती केल्याने, रशीया अमेरीकन निती विरोधात गेला आणि यांच्यात तेंव्हापासुन शितयुध्द सुरु झाले त्यांनी आपआपले प्रस्थ वाढविण्यासाढी नव नविन गटांची स्थापना केली, त्यामध्ये सिटो, नाटो, वारसा इत्यादी त्याचा परिणाम जगात जे राज्य आपला विकास करुन ईच्छित होते, परंतू या दोन्ही देशाच्या बंधनात न राहता इतर सहकारी संघटना स्थापन करुन त्या माध्यमातून विकास व्हावा अशी अपेक्षा करत होते.

अशा राष्ट्रांनी युरोपीयन महासंघाची प्रेरणा घेऊन ओपॅक,आशियन आणि सार्क अशा प्रादेशिक सहकार्य करणाऱ्या संघटनांची निर्मिती केली.

सार्क :—

युरोपियन महासंघाच्या धर्तीवर, एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या उद्दिष्टाने दक्षिण आशिया क्षेत्रातील राज्यांनी, त्यामध्ये भारत, पाकीस्तान, नेपाळ, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदिव आणि भुतान एकत्र येऊन ८ डिसेंबर १९८५ ला सार्क (SAARC) ची स्थापना केली, आणि आज अफगणिस्तान २००७ ला सार्क सदस्य झाल्याने संघटनेची संख्या आठ झाली आहे.

सार्क सात देशाची परस्पर सहकार्यासाठी स्थापन झालेली आग्नेय आशीयाची राष्ट्रांची विभागीय सहकार्य संघटना आहे दक्षिण आशीया उपखंडातील सात राष्ट्रांमध्ये आर्थिक आणि व्यापारी एक सहकारी व्यासपिठ असावे अशी मूळ कल्पना प्रथम १९८० साली बांगला देशाचे तत्कालीन अध्यक्ष झिया–उर–रहेमान यांनी मांडली होती. त्यासाठी त्यांनी १९७७ ते १९८० या काळात भारत, पाकीस्तान,नेपाळ, श्रीलंका या देशांना भेटी दिल्या. त्यांच्या प्रयत्नना अनुसरुन प्रथमत: दक्षिण आशियाची देशांच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठक घेऊन त्यामध्ये कोणकोणत्या क्षेत्रात या देशांना सहकार्य करता येणे शक्य आहे यावर विचार विनिमय झाला. एप्रिल १९८१ मध्ये या राष्ट्रांच्या परराष्ट्र सचिवांची कोलंबो येथे पहिली बैठक झाली. त्यांनतर काढमांडू. नोव्हेंबर–१९८१, इस्लामाबाइ–१९८२,ढाका–मार्च १९८३ अशा तीन बैठका झाल्या. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्र्याची बैठक झाली त्यामध्ये संघटनेच्या एकात्मिक कृती कार्यक्रमाबाबत सहमती झाली. शेती (कृषी), ग्रामीण विकास, हवामान शास्त्र, आरोग्य, लोकसंख्या या क्षेत्रात सातही राष्ट्र परस्परांशी सहकार्य करुन शकतात यावर सातही राष्ट्रात एकमत झाले आणि शेवटी ७ व ८ डिसेंबर १९८५ ला बांग्लादेशाच्या राजधानित (ढाका) येथे सातही राष्ट्रप्रमुखांची बैठक झाली आणि त्यात सार्कच्या स्थापनेवर शिक्कामोर्तब झाले.

सन १९८५ पासुन आजपर्यंत सार्क संघटनेने आर्थिक क्षेत्रात सहकार्य वृध्दीगंत केले. सोबतच महिला व बालकल्याण, शांतता, विकास,दारिद्र्य निर्मूलन, पर्यावरण संरक्षण अशा विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यात २००६ मध्ये दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) या संघटनेची स्थापना करुन मुक्त व्यापारास चालना दिली. एकंदरीत सार्क इतर क्षेत्रात मध्ये उत्तम कार्य करत असल्याचे त्यांच्या मागील कार्यावरुन निदर्शनास येते. परंतू तरीही सार्कला जगातील इतर यशस्वी प्रादेशिक संघटनासारखे यश अद्यापही मिळालेले नाही. त्याचे प्रमुख कारण काय ? याचा शोध जेंव्हा घेतला जातो तेंव्हा सदस्य राष्ट्रामध्ये आपसात असलेले टोकाचे वैमनस्य हे प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास येते. या वैमनस्याचे प्रमुख कारण पाकीस्तानकडून दहशतवाद रोखण्यासाठी कोणताही प्रतिसाद न मिळता उलट त्याला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे अनेक वेळा पुराव्यानिशी स्पष्ट केले आहे. तरीही दहशतवादी कारवाया अजून थांबलेल्या नाहीत त्यात सार्कने वेळोवेळी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्याचा आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येईल.

दहशतवात थांबविण्यासाठी सार्कचे प्रयत्न :–

भारत,पाकीस्तान,श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगणिस्तान आदी सार्क संघटनेची सदस्य राष्ट्र दहशतवादाच्या समस्येला तोंड देत आहेत. काठमांडू येथे नोव्हेंबर १९८७ मध्ये झालेल्या सार्कच्या तिसऱ्या शिखर संमेलनात दहशवाद दडपून टाकण्याच्या करारावर सर्व सदस्य राष्ट्रांनी सहया केल्या, म्हणजे दहशवाद दडपून टाकण्याच्या कराराला मंजुरी दिली. दहशतवादी गुन्ह्यांबाबत आंतरराष्ट्रीय कायद्यात नमुद असलेल्या मुलभूत सिध्दांताची दक्षिण आशीया या प्रदेशात अंमलबजावनी करण्याचे या कराराने सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्य केले. उदा. दहशवादी कृतीबाबतच्या माहितीचे आदान–प्रदान सर्व सदस्य राष्ट्रांनी करणे, अंमली पदार्थाचा चोरटा व्यापार, हवाला मार्गाने पैशांची देवाणघेवाण, अन्य प्रकारचे संघटित गुन्हे आणि दहशवादी संघटना यांच्यात परस्पर संबंध आहेत. दहशवादाला पायबंद घालावयाचा असेल तर या सर्व प्रकारच्या गुन्हयांवरही हल्ला करणे व त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेवुन यामध्ये २००२ ला सुधारणा करण्यात आली सोबतच २००४ मध्ये इस्लामाबादच्या १२ व्या शिखर परिषदेत सदस्य राष्ट्रांनी दहशतवादी संघटनाच्या आर्थिक संसाधनावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक करार केला. ऑगस्ट २००८ च्या बैठकीत दहशवाद व तत्सम गुन्हयातील माहितीचे देवाण घेवाण करण्याच्या दृष्टिने पंधराव्या सार्क परिषदेत Convention on Mutual Legal Assistance Treaty (MALT) करण्यात आला आणि पुन्हा नोंव्हेंबर २००८ मध्ये भारतातील मुंबई शहरात फार मोठा दहशतवादी हल्ला घडून आला. यामधुन पुन्हा भारत–पाक संबंध ताणल्या गेले आणि भारताने UNO पासुन सार्क पर्यंत सर्व ठिकाणी या हल्याला पाकीस्तानने मदत केल्याचे निदर्शनास आणुन दिले.

याशिवाय नोंव्हेंबर २०१६ मध्ये पाकीस्तान येथे होणाऱ्या सार्क परिषदेत भारतात पाकस्कृत झालेल्या उरी हल्ल्याच्या निषेधार्त भारत, बांग्लादेश, भूतान व अफगाणिस्तान या राज्यांनी सहभाग नाकारला. सोबतच सार्कच्या प्रत्येक संमेलनात दहशवादावर प्रतिबंध घालण्यासाठी हा विषय अजेंडयावर असतो. त्याचाच प्रत्यय म्हणून यावर्षी २४ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या सार्कच्या ऑनलाईन बैठकीमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री श्री जयशंकर यांनी पाकचे नाव न घेता दहशतवादाला खतपाणी घालण्याऱ्यांनी बंद करावे व दहशवादाला पायबंद घालण्यासाठी मदत करावी असे नमुद केले. असे सार्कने दहशवाद थांबविण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत, आणि प्रत्येक बैठकीमध्ये दहशवाद ही समस्या अजेंडयावर ठेवली जाते.

निष्कर्ष –

१९८७ पासनुच्या तिसऱ्या शिखर संमेलनापासुन २०२० च्या शिखर संमेलनापर्यंत जवळपास सर्वच संमेलनात शिखर परिषदांच्या कार्यक्रम पत्रीकेवर दहशवाद हा विषय असल्याचे दिसून येते व प्रत्येक बैठकीत राष्ट्रप्रमुखांनी एकमताने दहशतवादावर ठराव मंजुर केलेले आहेत. परंतू अद्यापही दहशवादाच्या प्रभावातून सार्क संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांची सुटका झालेली नाही. कारण ते आमलात आणण्यासाठी त्या त्या राज्यातील विधिमंडळानी त्याला पुरेशा प्रमाणात मंजुरी दिल्याचे आढळून येत नाही त्यासाठी सार्कने कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. आज एक प्रादेशिक संघटना म्हणून सार्कचे योगदान नक्कीच चांगले आहेत परंतू सदस्य राष्ट्रांनी आपसामध्ये सार्कच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अमंलबजावणी प्रामाणिकपणे करणे अपेक्षित आहे. तेंव्हाच दहशतवाद रोखण्यासाठी सार्क यशस्वी होऊ शकेल अशी आशा आहे.

संदर्भ –

१. *रासम वासंती व खापरे करिअप्पा (२०११) आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारण, फडके प्रकाशन कोल्हापुर.*

२. *पाटील व्ही.बी. जुलै (२०१२) भारताचे परराष्ट्र धोरण, के सागर पब्लीकेशन, पुणे*

३. *Countering Terrorism in South Asia : Strengthening Multilateral Engagement, Eric Ros and, Naureen Choudhary Fink, and Jason Ipe (May-2009)(ipinst.org/wp-content/uploads/ publications/ct_in_south_asia_epub.pdf)*